खबर संक्षेप

दो बाइकों की भीषण भिड़ंत में 2 युवकों की दर्दनाक मौत



उमरिया। सडक़ सुरक्षा के तमाम दावों और जागरूकता अभियानों को ठेंगा दिखाती तेज रफ्तार की हवस ने एक बार फिर दो चिरागों को बुझा दिया। जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत जरहा चौराहा के समीप कौडिय़ा पुल के पास उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब रफ्तार के जुनून में दौड़ रही दो मोटर साइकिलें आपस में इस कदर टकराईं कि देखने वालों की रूह कांप उठी। इस भीषण और दर्दनाक सडक़ हादसे में दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।मिली जानकारी के मुताबिक, पल्सर बाइक पर सवार होकर अमृतलाल बैगा उम्र 25 वर्ष, कैलाश बैगा उम्र 24 वर्ष और सागर बैगा उम्र 30 वर्ष उमरिया से घुलघुली की दिशा में जा रहे थे। तभी सामने से अपने गांव भुंन्डी की ओर लौट रहे मंगल कोल और उनके नाती शंकर कोल की बाइक से कौडिय़ा पुल के पास सीधी और जोरदार भिड़ंत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो भिड़ंत इतनी भीषण थी कि सवार हवा में उछलकर दूर जा गिरे। हादसे के भयावह मंजर के बीच अमृतलाल बैगा और कैलाश बैगा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में हडक़ंप मच गया और स्थानीय लोगों का हुजूम जमा हो गया। सूचना मिलते ही डायल 112 और नौरोजाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल सागर बैगा को आनन-फानन में जिला अस्पताल उमरिया रवाना किया गया, वहीं मंगल कोल और उनके नाती भी उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। इस भीषण हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर दुर्घटना के कारणों की जांच और वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर रफ्तार का यह खूनी खेल और कितनी जानें लेगा?

विश्वविद्यालय में छात्रों का फूटा गुस्सा

शहडोल। पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में फैली अव्यवस्थाओं और मूलभूत सुविधाओं के अकाल को लेकर विद्यार्थियों का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के जिलाध्यक्ष सौरभ तिवारी के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं ने विभाग परिसर के सामने तीन दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। विद्यार्थियों का कहना है कि लंबे समय से शैक्षणिक संसाधनों और बेहतर माहौल के लिए गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन मौन बैठा हुआ है।
विद्यार्थियों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि समाजशास्त्र विभाग लंबे समय से बदहाली का दंश झेल रहा है। विभाग का भवन अत्यंत जर्जर स्थिति में है, जिससे हर समय सुरक्षा का खतरा मंडराता रहता है। इसके अलावा अध्ययन कक्षों की खराब स्थिति, आधुनिक शिक्षण पट्टिकाओं की कमी और बुनियादी सुविधाओं के न होने से पठन-पाठन का कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है। शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थियों को धरने पर बैठने के लिए विवश होना, प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।धरना प्रदर्शन के दौरान उस समय स्थिति और तनावपूर्ण हो गई जब विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय मौके पर पहुंचे। जमीन पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे छात्र-छात्राओं को उम्मीद थी कि प्रशासनिक प्रमुख उनकी बात सुनेंगे। परंतु एनएसयूआई का आरोप है कि कुलपति महोदय विद्यार्थियों की समस्याओं पर ध्यान दिए बिना ही वहां से चले गए। इस उदासीन रवैये से आक्रोशित छात्रों का गुस्सा और भडक़ उठा।

मायके ले जाने की बात पर हुआ था विवाद, वारदात के बाद से संदिग्ध पति फरार

बंद कमरे में मिले मां-बेटी के सड़े-गले शव

मकान से उठी सड़ांध तो खुला कातिल पति का खौफनाक राज





शहडोल।
अपराध और हैवानियत की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जिले के गोहपारू थाना अंतर्गत ग्राम नवागांव में बंद दरवाजे और कड़े पहरे के पीछे छिपे एक खौफनाक गुनाह का पर्दाफाश हुआ है। एक बंद मकान से आ रही असहनीय दुर्गंध ने जब ग्रामीणों का ध्यान खींचा, तो मां-बेटी के नरक बने शव बरामद हुए। करीब पांच दिन पुराने इन सड़े-गले शवों की हालत देखकर मौके पर पहुंचे लोगों की रूह कांप गई। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में वारदात की सुई सीधे मृतका के फरार पति की ओर घूम गई है, जो घटना के बाद से ही घर के बाहर ताला लगाकर रफूचक्कर है।

5 दिन पुराने बताए जा रहे शव, बाहर लगा था ताला, अहमदाबाद से डायल-112 को मिली सूचना, ताला तोडक़र अंदर दाखिल हुई पुलिस

अहमदाबाद से फोन पर हरकत में आई पुलिस

वारदात का पर्दाफाश गुरुवार को हुआ, जब नवागांव स्थित एक मकान के आस-पास से अचानक तेज सड़ांध आने लगी। बदबू इतनी भीषण थी कि पड़ोसियों का सांस लेना दूभर हो गया। अनहोनी की आशंका के चलते ग्रामीणों ने तत्काल मृतका के रिश्तेदारों को इसकी भनक दी। गुजरात के अहमदाबाद में रह रहे रिश्तेदार ने बिना वक्त गंवाए सीधे आपातकालीन नंबर डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी।
खबर मिलते ही गोहपारू थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। घर के मुख्य द्वार पर बड़ा ताला लटका हुआ था। पुलिस ने जब ताला तोडक़र कमरे के भीतर कदम रखा, तो अंदर का मंजर रोंगटे खड़े करने वाला था। कमरे में दो महिलाओं के शव पड़े हुए थे, जो सड़-गल चुके थे। मृतकों की पहचान रुचि रजक उम्र 30 वर्ष और उसकी मां सावित्री रजक उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई। शवों की भयावह स्थिति को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि दोनों की जीवनलीला करीब 5 दिन पहले ही समाप्त कर दी गई थी।

बेटी को मायके ले जाने आई थी मां

तफ्तीश में जो तथ्य छनकर सामने आए हैं, वे बेहद दिल दहला देने वाले हैं। मृतका रुचि का मायका सीधी जिले के मझौली में स्थित है। वर्ष 2025 में उसकी शादी नवागांव के युवक से हुई थी, जिसके बाद से वह अपने ससुराल में रह रही थी। गत रविवार को रुचि की मां सावित्री अपनी बेटी को मायके ले जाने के उद्देश्य से नवागांव पहुंची थी। बताया जा रहा है कि बेटी को मायके ले जाने की इसी बात पर ससुराल में नोकझोंक शुरू हो गई। पति इस बात से बेहद खफा था। रविवार की रात दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि आशंका जताई जा रही है कि पति ने अपना आपा खो दिया और मां-बेटी दोनों को मौत के घाट उतार दिया।

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, आरोपी की तलाश तेज

ताला लगाकर फरार हुआ संदिग्ध

गांव वालों ने पुलिस को बताया कि रविवार की रात रुचि के पति को आखिरी बार गांव में संदिग्ध हालत में घूमते और बाहर जाते देखा गया था। उसके बाद से ही वह गांव से गायब है। घर के बाहर ताला ठोककर फरार होना उसके गुनाहगार होने की ओर साफ इशारा कर रहा है। घटना की भयावहता को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की विशेषज्ञ टीम को मौके पर बुलाया। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से बारीक साक्ष्य, उंगलियों के निशान और अन्य महत्वपूर्ण सुराग एकत्र किए हैं। दोनों शवों का पंचनामा बनाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों और समय का आधिकारिक खुलासा हो सकेगा।

कातिल की गिरफ्तारी के लिए बिछाया जाल

मामले की गंभीरता पर सीएसपी राजेंद्र मोहन दुबे ने बताया कि प्रारंभिक जांच-पड़ताल और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर रुचि का पति ही इस दोहरे हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध है। वारदात के बाद से वह लगातार फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और पूछताछ के बाद इस सनसनीखेज हत्याकांड की एक-एक परत खोल दी जाएगी।

हाईवे पर जेबें भर रहे थे खाकीधारी

वीडियो वायरल होते ही कप्तान ने दिखाया बाहर का रास्ता

रिश्वतखोर पुलिसकर्मी चालक को दे रहे थे छुपाव का ज्ञान

शहडोल। सडक़ों पर खाकी का खौफ जनता और अपराधियों में हो न हो, लेकिन लगता है वर्दीधारियों की जेबें गर्म करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अक्षय पात्र बन चुके हैं। सोहागपुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर सुरक्षा और कानून का पाठ पढ़ाने वाले पुलिस महकमे की साख उस वक्त फिर नीलाम हो गई, जब एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) साहब सरेआम मालवाहक वाहन चालकों से अपनी जेब भरते कैमरे में कैद हो गए। वीडियो सोशल मीडिया की गलियों में क्या तैरा, पूरी पुलिसिया साख की धज्जियां उड़ गईं। मामला जैसे ही कप्तान साहब के पास पहुंचा, उन्होंने बिना देर किए दोनों दागी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर ब्यौहारी थाने का रास्ता दिखा दिया है।

ज्ञान भी दे रहे थे एएसआई साहब!

प्रसारित वीडियो में सोहागपुर थाने में तैनात एएसआई जवाहर लाल राय एक पिकअप चालक के पास पूरी धौंस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वीडियो के दृश्यों में साफ दिखाई दे रहा है कि साहब पहले चालक से



कडक़ड़ाते नोट लेते हैं और बड़ी नजाकत से अपनी जेब के हवाले कर देते हैं। हद तो तब हो गई जब नोट जेब में डालते ही एएसआई साहब चालक को हिदायत देने लगे— मोबाइल बंद रखा कर, ज्यादा मोबाइल मत चलाया कर! यानी डाका भी डालेंगे और पकड़ा न जाएं, इसके लिए ज्ञान की गंगा भी बहाएंगे, स्थानीय लोगों की मानें तो इस हाईवे पर मालवाहक चालकों को रोककर जेबें ढीली कराना कोई नई बात नहीं है, बस फर्क इतना है कि इस बार साहब कैमरे की आंख से खुद को बचा नहीं सके।

दो पुलिसकर्मी तत्काल प्रभाव से निलंबित

जैसे ही यह शर्मनाक वीडियो शहडोल पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के संज्ञान में आया, उन्होंने विभाग में अनुशासनहीनता और अनैतिक आचरण पर जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाते हुए 08 अक्टूबर को निलंबन का फरमान जारी कर दिया। सोहागपुर थाने के एएसआई को वीडियो में रिश्वतखोरी और संदिग्ध आचरण प्रथम दृष्टया साबित होने पर तत्काल निलंबित कर ब्यौहारी थाने अटैच कर दिया गया। बुढ़ार थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक चेतराम कौशिक पर भी गाज गिरी। बिना थाना प्रभारी को बताए वारंटी पकडऩे के नाम पर फर्जी रवानगी तो डाली, लेकिन न तो वारंटी मिला और न ही कोई रिपोर्ट दर्ज हुई। उलटे संदिग्ध गतिविधियों का वीडियो सामने आते ही साहब को भी निलंबित कर ब्यौहारी थाने की हवा खाने भेज दिया गया।

डीएसपी करेंगे परत-दर-परत जांच

पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने दो टूक चेतावनी दी है कि खाकी की आड़ में वसूली और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। दोनों मामलों की गंभीरता को देखते हुए उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) स्तर के अधिकारियों को पृथक-पृथक विभागीय जांच सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आते ही दोषियों के खिलाफ और कड़ा वैधानिक प्रहार किया जाएगा। कप्तान के इस आक्रामक रुख से भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की रातों की नींद उड़ गई है।

नवरात्र पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट चप्पे-चप्पे पर होगी निगरानी

पदभार संभालते ही एक्शन मोड में एसडीओपी ललित गठरे

उमरिया। जिले के बिरसिंहपुर पाली के नवागत अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) ललित गठरे ने पदभार ग्रहण करते ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सुचारू कानून व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प दोहराया है। पूर्व में सीएसपी खंडवा, असिस्टेंट कमांडेंट तथा सिवनी में एसडीओपी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ललित गठरे ने साफ कर दिया है कि अपराध नियंत्रण और आम जनता की सुरक्षा ही उनकी सर्वोपरि प्राथमिकता होगी।
पदभार संभालने के उपरांत नवागत एसडीओपी ने मां बिरासिनी देवी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आगामी नवरात्र और दशहरा पर्व को देखते हुए उन्होंने मंदिर परिसर और प्रमुख स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। शांति समिति की बैठक के दौरान आयोजकों को सुरक्षा मानकों,



सीसीटीवी और पांडाल प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी निभाने की हिदायत दी गई है। साथ ही डीजे संचालकों को तय मापदंडों का पालन करने और अश्लील व फुहड़ गाने न बजाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
एसडीओपी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक या शांतिभंग करने वाले पोस्ट साझा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साइबर टीम हर गतिविधि पर बारीक नजर रख रही है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। क्षेत्र में पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। एसडीओपी



ललित गठरे ने कहा कि जनसंपर्क कार्यालय से अधिकृत और मान्यता प्राप्त पत्रकारों की प्रामाणिक सूची प्राप्त की जाएगी। बिना पात्रता अपने वाहनों पर अवैध रूप से प्रेस या मीडिया लिखकर घूमने वालों और डरा-धमकाकर वसूली करने वाले असमाजिक तत्वों की गहन चेकिंग कर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एसडीओपी ने आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करने तथा भयमुक्त माहौल निर्मित करने का भरोसा दिलाया है।

कांग्रेस का हल्ला बोल, बांहों पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध

शहडोल। लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की रक्षा की अलख जगाते हुए शहडोल जिला कांग्रेस कमेटी ने 08 अक्टूबर को पूरे जिले में काला दिवस के रूप में मनाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला मुख्यालय स्थित गांधी चौक पर दर्जनों कांग्रेसजनों ने अपनी बांहों पर काली पट्टियां बांधकर केंद्र सरकार और प्रशासनिक रवैये के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय अवस्थी के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। जिलाध्यक्ष अजय अवस्थी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित इंडिया गठबंधन के सांसद चुनाव आयोग से निष्पक्षता और जवाबदेही की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जंतर-मंतर जा रहे थे। लेकिन सत्ता के इशारे पर पुलिस ने उनके साथ अभद्रता और बल प्रयोग किया। जन प्रतिनिधियों पर लाठियां चलाना और उन्हें हिरासत में लेना लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा का खुला चीरहरण है।
जिला मुख्य प्रवक्ता पीयूष शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने की चाहे जितनी कोशिश कर ली जाए, कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। शहडोल के गांधी चौक पर उमड़े कांग्रेसी दिग्गजों ने एक स्वर में कहा कि यह काला दिवस देश की लोकतांत्रिक आत्मा पर हुए आघात के खिलाफ एक चेतनावंत हुंकार है।
इस जोरदार सियासी प्रदर्शन में पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता, नीरज द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष कुलदीप निगम, वरिष्ठ नेता सुनील खरे, मुख्य प्रवक्ता पीयूष शुक्ला, अनुज मिश्रा, नगर अध्यक्ष प्रभात पाण्डेय, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष आशीष तिवारी, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सौरभ तिवारी, पूर्व पार्षद जितेंद्र सिंह, प्रीतमदास सोनी, संतोष पाण्डेय, अजीत सोनी, हीरालाल प्रजापति, रामनरेश तिवारी, सबी खान बंटी, इबरार खान, कुंज बिहारी द्विवेदी, इकबाल खान, राजेश बैगा, रज्जन खान, उमाकांत अठ्या, संजय पटेल, आशीष द्विवेदी, आशु सिंह, शिवांशु साहू, आरुष तिवारी, गुलशन, अशोक तिवारी, धन्नू बर्मन, वरुण पाल, शोभराज नागपाल और गोविंद प्रजापति सहित बड़ी तादाद में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जंतर-मंतर की धमक से जयसिंहनगर में गर्जी कांग्रेस

वोट चोर गद्दी छोड़ो के नारों से गूंजा बस स्टैंड, मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी हिलाने की हुंकार

शहडोल। दिल्ली के जंतर-मंतर पर 7 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई की गूंज अब जयसिंहनगर की सडक़ों पर भी सुनाई देने लगी है। केंद्र सरकार की कथित तानाशाही और लोकतंत्र के चौथे खंभे को कुचलने की नीयत के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जयसिंहनगर ने मोर्चा खोलते हुए जमकर काला दिवस मनाया। बस स्टैंड परिसर में ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट राजेश मिश्रा की अगुवाई में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इक_ा होकर जमकर नारेबाजी की। वोट चोर गद्दी छोड़ो और तानाशाही नहीं चलेगी के नारों से पूरा बस स्टैंड इलाका थर्रा उठा। विरोध प्रदर्शन के



दौरान कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रहे, जिनसे तत्काल इस्तीफे की मांग की गई।

कागजी नहीं, जनादेश की चोरी हो रही है

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एडवोकेट राजेश मिश्रा ने सीधे लहजे में कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने और जनादेश पर डाका डालने के लिए खाकी का सहारा ले रही है। जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे शीर्ष नेताओं पर पुलिसिया डंडा चलवाना इस बात का सबूत है कि सत्ता में बैठे लोग लोकतंत्र से डरे हुए हैं। उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि वोट चोरी और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन अब बर्दाश्त से बाहर है। प्रदर्शन में रोहिणी शुक्ला, रामनिवास पयासी, परसुराम द्विवेदी, धर्मेंद्र भाटिया, उमाकांत द्विवेदी, महेंद्र गुप्ता, जगदंबा तिवारी, अजय जायसवाल, हनुमान उपाध्याय, राममनोहर पाल, छोटेलाल नामदेव, लाला यादव और बिन्नू भाटिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ अपनी हुंकार भरी।

विश्वविद्यालय परिसर में गूंजा वायु सेना के शौर्य का जयघोष

शहडोल। पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में सेवा संकल्प अभियान 2026 के तत्वावधान में भारतीय वायु सेना दिवस का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार ने नीले आकाश के प्रहरियों के अदम्य शौर्य, साहस और राष्ट्र सेवा के प्रति उनके समर्पण को नमन किया।समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में परिसर प्रभारी प्रो. गीता सराफ उपस्थित रहीं। वहीं विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त वायु सैनिक एस. मजूमदार ने अपने प्रेरक उद्बोधन में भारतीय वायु सेना के गौरवशाली इतिहास और सीमाओं की रक्षा में जांबाज सैनिकों के अविस्मरणीय योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रो. मनीषा तिवारी एवं नोडल अधिकारी डॉ. जी. एस. सांडया सहित प्राध्यापक, एनसीसी कैडेट्स और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को देशभक्ति, अनुशासन, निष्ठा और राष्ट्र सेवा के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। छात्र-छात्राओं ने भी वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का दृढ़ संकल्प लिया।

खबर संक्षेप

भालूमाड़ा के पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल में मनाया कृमि मुक्ति दिवस



बदरा/जमुना। पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल भालूमाड़ा में कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कक्षा 1 से 10 वीं तक के छात्र-छात्राओं को कृमिनाशक दवा खिलाई गई। विद्यार्थियों को कृमि संक्रमण से बचाव, स्वच्छता और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य सतीश सिंह सहित शिक्षक लक्ष्मी नाथ तिवारी, कंचन बावरिया, देवेंद्र तिवारी, उमाशंकर और सुधा शुक्ला सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

अनूपपुर सेवा संकल्प अभियान के तहत दिव्यांग छात्रावास में बच्चों को बांटे फल, गूंजे प्रेरणा गीत



बदरा/जमुना। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, जिला अनूपपुर के तत्वावधान में सेवा संकल्प अभियान (सेवा में मेरा योगदान) के अंतर्गत जिला दिव्यांग छात्रावास अनूपपुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान परिषद के पदाधिकारियों एवं समाजसेवियों ने छात्रावास के बच्चों से आत्मीय भेंट कर उनका हालचाल जाना और उन्हें फल वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान जिला समन्वयक उमेश कुमार पाण्डेय ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके साथ मिलकर प्रेरणा गीत गाया, जिससे पूरे परिसर का माहौल अत्यंत ऊर्जावान और भावुक हो गया। इस अवसर पर जिला समन्वयक उमेश कुमार पाण्डेय, ब्लॉक समन्वयक फते सिंह, परिषद से जुड़ी नवांकुर संस्था नगर विकास प्रस्फुटन समिति पसान, कोशिश फाउंडेशन, आनंदम सोशल वेलफेयर सोसायटी धनगवां पूर्वी से दिनेश, ह्यमैनिटी केयर फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ सोसायटी के प्रतिनिधि पुष्पेन्द्र उपस्थित रहे। साथ ही छात्रावास के अधिकारी विनय मिश्रा, परामर्शदाता शिवानी सिंह, विक्रम सिंह, अनिल सिंह परिहार, प्रीति सिंह सीएमसीएलडीपी छात्र सहित छात्रावास का समस्त स्टाफ एवं बच्चे मौजूद रहे।

वार्ड नंबर 1 में बिना अनुमति पहली मंजिल की ढलाई

जयसिंहनगर में नियमों को ठेंगा दिखाकर धड़ल्ले से तन रही अवैध इमारत

सीएमओ की चेतावनी हवा-हवाई, नोटिस के बाद भी बंद नहीं हुआ निर्माण कार्य

शहडोल। स्थानीय नगर परिषद जयसिंहनगर इन दिनों अपनी अनोखी और सुस्त कार्यशैली को लेकर जबरदस्त चर्चा में है। निकाय क्षेत्र में नियम-कायदों की धज्जियां उड़ाकर अवैध निर्माण करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें नगर परिषद के नोटिस से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। प्रशासन कागजों पर शेर बन कर नोटिस थमा रहा है, और दूसरी तरफ संबंधित भू-स्वामी परिषद के इस कागजी फरमान को ठेंगा दिखाते हुए दिन-रात धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं। कार्रवाई के नाम पर केवल रस्म अदायगी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की नीयत और कार्यप्रणाली पर अब क्षेत्र की जनता सीधे सवाल खड़े कर रही है।

यह है पूरा मामला

मामला नगर परिषद जयसिंहनगर के वार्ड क्रमांक 01 का है, जहां बिना किसी वैध अनुमति के लगभग 15&30 (कुल 450 वर्गफुट) भूमि पर पहली मंजिल का निर्माण कार्य जोर-शोर से कराया जा रहा है। जब नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को अचानक नगर भ्रमण के दौरान इस अवैध कारनामे की भनक लगी, तो उन्होंने राजकुमार तिवारी और कमलेश तिवारी पिता जोधी तिवारी के नाम एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया कि उक्त स्थल पर बिना नगर परिषद की पूर्व स्वीकृति के निर्माण कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 का हवाला देते हुए इस निर्माण को



सीधे तौर पर दंडनीय अपराध करार दिया गया।

3 दिन की मोहलत, पर फरमान बेअसर

सीएमओ द्वारा जारी इस नोटिस में सख्त लहजे में हिदायत दी गई थी कि संबंधित व्यक्ति तीन दिवस के भीतर ऑटोमेटिक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के जरिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करे और निर्धारित शुल्क जमा करके भवन निर्माण की वैधानिक अनुमति प्राप्त करे। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई थी कि समय सीमा के भीतर आवेदन न करने पर मामले को अदालत में घसीटा जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भू-स्वामी की होगी, लेकिन मजेदार बात देखिए! चेतावनी की म्याद और कानून का डर केवल नगर परिषद की फाइलों तक ही सीमित रह गया। जमीनी हकीकत यह है कि नोटिस मिलने के बाद भी निर्माण स्थल पर न तो हथौड़े थमे और न ही राजमिस्त्री की कन्नी। काम वैसी ही र?तार से चालू है, मानो जयसिंहनगर में नगर परिषद नाम की कोई संस्था अस्तित्व में ही न हो।

नोटिस भेजा या सिर्फ खानापूर्ति की

खबर है कि इस नोटिस की प्रतियां शहडोल कलेक्टर, जयसिंहनगर तहसीलदार और नगर परिषद अध्यक्ष को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब प्रशासनिक महकमे के इतने बड़े-बड़े सूरमाओं तक बात पहुंच चुकी है, तब भी ज़मीन पर ईंट से ईंट जु?ने का सिलसिला क्यों नहीं रुका? क्या नगर परिषद का काम सिर्फ एक पन्ना थमाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना है? स्थानीय नागरिकों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश और हैरानी है कि आखिर किस अदृश्य शह पर यह अवैध निर्माण बेखौफ जारी है? क्या निकाय अधिकारी केवल इसलिए शांत बैठे हैं कि नोटिस जारी कर उन्होंने अपनी औपचारिकता पूरी कर ली, या फिर पर्दे के पीछे कोई खास मेहरबानी खेल खेल रही है?

अब आगे क्या करेंगी सोई हुई एजेंसियां

बिना नक्शा पास कराए और बिना अनुमति के तानी जा रही इमारतों पर अगर समय रहते पीला पंजा या कठोर कानूनी डंडा नहीं चला, तो जयसिंहनगर में नियम और कानून का मजाक बनना तय है। आम जनता अब टकटकी लगाए देख रही है कि बड़ी-बड़ी बातें करने वाली नगर परिषद इस खुले उल्लंघन पर कोई ठोस दंडात्मक कदम उठाती है या फिर इस फाइल पर भी धूल जमने के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्या जिम्मेदारों में इतनी हिम्मत बचेगी कि वे अवैध निर्माण को ध्वस्त करवा सकें, या फिर जयसिंहनगर में जिसकी लाठी, उसकी भैंस का कानून ही चलता रहेगा।

मानपुर में दुर्गोत्सव एवं दशहरा को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न





सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लिए गए अहम निर्णय

मानपुर। विधानसभा क्षेत्र में आगामी दुर्गोत्सव एवं दशहरा पावन पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने को लेकर गुरुवार को मानपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार ने की, जिसमें थाना प्रभारी मानपुर, नगर परिषद के प्रतिनिधि, जनपद सदस्य, पत्रकारगण, नगर के गणमान्य नागरिक, शांति समिति के सदस्य एवं विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों के आयोजक मौजूद रहे।

बैठक में सर्वसम्मति से कई अहम निर्णय

बिना अनुमति के कोई भी मूर्ति स्थापना नहीं होगी। सभी समितियों को एसडीएम कार्यालय से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित समय और निर्धारित डेसिबल में ही डीजे बजाने की अनुमति होगी। अश्लील गानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विसर्जन के लिए मुख्य मार्ग तय किया गया। विसर्जन के दौरान पुलिस बल, होमगार्ड और गोताखोरों की व्यवस्था रहेगी।

बिजली विभाग को जुलूस मार्ग पर लटकते तारों को दुरुस्त करने के निर्देशदिए गए। क्षेत्र का माहौल खराब करने वाले उपद्रवियों पर विशेष नजर रखी जाएगी साथ ही अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस तैनात रहेगी, अधिकारियों ने सभी समिति संचालकों से अपील की है कि वे आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें और प्रशासन का सहयोग करें अंत में थाना प्रभारी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का आवाहन किया। उक्त अवसर पर बैठक में मुख्यरूप से तहसीलदार अभय नंद शर्मा, थाना प्रभारी ब्रजकिशोर गर्ग, रामकिशोर चतुर्वेदी, हरीश विश्वकर्मा, अंबिका प्रसाद पयासी,सुरेश मुन्ना सिंह, राजनारायण भट्, दिनेश गुप्ता, रसिक खंडेलवाल, रामाभिलाष त्रिपाठी, कृष्ण कुमार उपाध्याय ,विकाश शुक्ला, विकाश गुप्ता,सजन कोल, हर्ष खंडेलवाल, अब्बू खंडेलवाल, म नोज श्रीवास्तव, महेश मिश्रा, कुश सिंह परिहार, जय प्रकाश शर्मा, राजू गुप्ता पवन गुप्ता, बिहारी प्रजापति, केदार सिंह आदि सैकड़ों की संख्या में लोग बैठक में पहुंच कार्यक्रम को सफल बनाए



मुख्यमंत्री ने 50 हजार रुपये का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

मानपुर के लाल रामकमल पयासी को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2026

मानपुर। नगर परिषद मानपुर के वार्ड क्रमांक 5 निवासी एवं दक्षिण शहडोल वनमंडल में वनरक्षक (डॉग हैंडलर) के पद पर पदस्थ रामकमल पयासी को वर्ष 2026 के वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें 7 अक्टूबर 2026 को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सागर में आयोजित चीता रिलीज कार्यक्रम के मंच पर प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्री पयासी को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 50 हजार रुपये का चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।प्रशस्ति पत्र में उल्लेख किया गया है कि श्री पयासी ने अपने व्यावसायिक कौशल का प्रभावी उपयोग करते हुए वन एवं वन्यजीव अपराध प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी, वन्यजीव रेस्क्यू तथा शिकार की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में उत्कृष्ट योगदान दिया। उनके कार्यों से प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिली। प्रशस्ति पत्र पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक डॉ. समीता राजोरा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख शुभरंजन सेन के हस्ताक्षर हैं।

परिवार और मानपुर में खुशी का माहौल

रामकमल पयासी की इस उपलब्धि से उनके परिवार के साथ-साथ मानपुर क्षेत्र में भी खुशी का माहौल है। उनके पिता श्री राम नारायण पयासी जनपद पंचायत मानपुर में पंचायत इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। बेटे की उपलब्धि पर परिवारजनों, शुभचिंतकों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई दी है।

आदर्श युवा ग्राम सभा में विद्यार्थियों ने जीवंत किया लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप



पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक में हुआ आयोजन

अमरकंटक। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक, जिला अनूपपुर में 7 सितंबर को प्राचार्य श्रीमती अर्चना सिंह के कुशल मार्गदर्शन में आदर्श युवा ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं नवोदय विद्यालय समिति के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने ग्राम सभा की कार्यप्रणाली को सजीव रूप में प्रस्तुत कर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बारीकियों को समझने का परिचय दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण उपाध्याय उपस्थित रहे। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अर्चना सिंह ने पुष्पगुच्छ एवं श्रीफल भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। आदर्श युवा ग्राम सभा के दौरान विद्यार्थियों ने सरपंच, सचिव, कृषि सहायक, युवा प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक एवं ग्रामवासी की भूमिकाओं का निर्वहन किया। उन्होंने ग्राम सभा की कार्यवाही को वास्तविक स्वरूप प्रदान करते हुए ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। विद्यार्थियों ने पेयजल, स्वच्छता, खाद-बीज वितरण, प्रधानमंत्री आवास, सड़क एवं नाली निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बेरोजगारी तथा कचरा प्रबंधन जैसे जनजीवन से सीधे जुड़े मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से उठाया। संवाद एवं प्रश्नोत्तर के माध्यम से विद्यार्थियों ने यह भी प्रदर्शित किया कि ग्राम स्तर पर विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम सभा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है।

मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार श्रवण उपाध्याय ने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय में प्राप्त इस प्रकार का व्यावहारिक अनुभव विद्यार्थियों को भविष्य में सामाजिक सरोकारों के प्रति अधिक जागरूक और उत्तरदायी नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करता है। प्राचार्य श्रीमती अर्चना सिंह ने कहा कि आदर्श युवा ग्राम सभा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे विद्यार्थियों को वास्तविक प्रशासनिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त होता है और उनमें समाज एवं राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना मजबूत होती है। कार्यक्रम के प्रभारी महेश्वर द्विवेदी, पीजीटी इतिहास रहे। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने ग्राम सभा की कार्यवाही का प्रभावशाली एवं अनुशासित प्रस्तुतीकरण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में रमेश कुमार सिंह, टीजीटी सामाजिक विज्ञान, सुश्री साधना सुमन, पीजीटी भूगोल तथा आशीष, पीजीटी अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों ने न केवल ग्राम स्तर की समस्याओं और उनके समाधान की संभावनाओं को समझा, बल्कि लोकतंत्र में संवाद, सहभागिता और सामूहिक निर्णय की महत्ता को भी आत्मसात किया। आयोजन ने विद्यालय परिसर में ग्रामीण लोकतंत्र की उस तस्वीर को साकार किया, जिसमें युवा पीढ़ी अपने दायित्वों और सामाजिक सरोकारों के प्रति सजग दिखाई दी।

टीबी मुक्त 144 पंचायतों के सरपंच सम्मानित, जोश टीम का शुभारंभ

कोतमा। जिले को टीबी मुक्त बनाने की मुहिम में ग्राम पंचायतों की भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से गुरुवार को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले की 144 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सम्मानित किया गया। इनमें तीन ग्राम पंचायतों को स्वर्ण श्रेणी में स्थान मिला है। मंत्री रामलाल रोतेल की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में टीबी उन्मूलन अभियान में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य विभाग और मैदानी अमले की भूमिका को रेखांकित किया गया। पंचायत स्तर पर जागरूकता बढ़ाने, टीबी के संभावित मरीजों की पहचान कर समय पर जांच कराने और उपचार से जोड़ने में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी को अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी बताया गया। कार्यक्रम के दौरान टीबी उन्मूलन अभियान को जनभागीदारी से जोड़ने के लिए जोश टीम का भी शुभारंभ किया गया। टीम के सदस्यों को उनकी पहचान और प्रोत्साहन के लिए पहचान पत्र, टी-शर्ट, टोपी और मग प्रदान किए गए। टीम के माध्यम से गांवों में टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने, संदिग्ध मरीजों को जांच और उपचार के लिए प्रेरित करने तथा अभियान में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत स्तर पर टीबी संदिग्ध मरीजों की समय पर जांच, उपचार की निरंतर निगरानी और जरूरतमंद मरीजों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा



कि केवल स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आम लोगों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। जिले की 144 पंचायतों का टीबी मुक्त श्रेणी में शामिल होना इस दिशा में किए गए सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया गया। अधिकारियों ने शेष क्षेत्रों में भी इसी तरह की जनभागीदारी बढ़ाने और टीबी उन्मूलन अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता जताई। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अलका तिवारी, जिला क्षय अधिकारी डॉ. एससी राय, जिला कार्यक्रम प्रबंधक शिवेंद्र द्विवेदी, जिला लेखा प्रबंधक रामसेवक अहिरवार, जिला कार्यक्रम समन्वयक सिम्मी वानखेड़े सहित राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की टीम और जिले की टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जिले को टीबी मुक्त बनाने के अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने का आहवान किया गया।

अमरकंटक के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों से रूबरू हुए नवोदय के विद्यार्थी

नर्मदा मंदिर में दर्शन-पूजन कर विद्यार्थियों ने जाना अमरकंटक का धार्मिक एवं प्राकृतिक महत्व

अमरकंटक। मां नर्मदा की उद्गम स्थली एवं प्रदेश के प्रमुख धार्मिक-आध्यात्मिक तीर्थ स्थल पवित्र नगरी अमरकंटक में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, मऊ जिला शहडोल के कक्षा सातवीं के छात्र-छात्राओं का एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण दल पहुंचा। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने अमरकंटक के प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों का अवलोकन कर उनके ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक महत्व की जानकारी प्राप्त की। विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती दिव्या त्रिपाठी, पीईटी अपर्णा गुरु एवं बलवीर वर्मा सहित छह शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों के मार्गदर्शन में कक्षा सातवीं के लगभग 75 छात्र-छात्राओं ने अमरकंटक के विभिन्न प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया। विद्यार्थियों ने मां नर्मदा मंदिर पहुंचकर दर्शन-पूजन किया तथा नर्मदा उद्गम स्थल के धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने अमरकंटक के प्रमुख पर्यटन एवं तीर्थ स्थलों को देखा और वहां की प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को करीब से समझा। विभिन्न स्थलों पर विद्यार्थियों ने अपनी जिज्ञासाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा भ्रमण को पुस्तकीय ज्ञान के साथ प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ने का प्रयास किया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किए जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों को वास्तविक परिवेश में समझने और स्थानीय इतिहास, संस्कृति, पर्यावरण एवं धार्मिक परंपराओं से परिचित होने का अवसर मिलता है। बताया गया कि इसके पूर्व पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मऊ के विद्यार्थियों का भी अमरकंटक शैक्षणिक भ्रमण हो चुका है। एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने अनुशासन एवं उत्साह के साथ विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया।

खबर संक्षेप

मॉडल रोड की जद में सामान समेटने लगे लोग

धनपुरी। शहर में मॉडल रोड और सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई अब लोगों के घर-दुकानों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। नगरपालिका से आजाद चौक होते हुए नरगडा नाला से बघइया नाला और बघइया पुल के आगे तक करीब 2 किलोमीटर हिस्से में सड़क के दोनों ओर 35-35 फीट क्षेत्र चिन्हित किया गया है। इस दायरे में करीब 250 घर और दुकानें प्रभावित होने की स्थिति में हैं। चिन्हांकन के बाद अब प्रभावित लोग खुद ही अपने घर-दुकानों से सामान निकालने और छुट-पुट निर्माण हटाने लगे हैं।मशीन से टूटने पर ज्यादा नुकसान का डरप्रभावित लोगों में सबसे बड़ी चिंता मशीन से होने वाली कार्रवाई को लेकर है। लोगों का कहना है कि यदि जेसीबी या अन्य मशीनों से निर्माण तोड़ा गया तो दीवारों के साथ घर-दुकान में रखा सामान, दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर और अन्य सामग्री भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसी डर से कई लोग पहले ही सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं और जहां संभव है, अपने हाथों से निर्माण का हिस्सा हटा रहे हैं।35 फीट के चिन्हांकन से बढ़ी बेचैनीसड़क के दोनों ओर 35 फीट क्षेत्र चिन्हित किए जाने के बाद प्रभावित परिवारों में कार्रवाई को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। कई घर और दुकानें लंबे समय से इस क्षेत्र में संचालित हैं। व्यापारियों के सामने दुकान खाली करने के साथ सामान सुरक्षित रखने की चुनौती है, वहीं रहवासियों को मकान के प्रभावित हिस्से को लेकर चिंता बनी हुई है। **लोगों की मांग**—पहले स्पष्ट हो कार्रवाई की स्थितिस्थानीय लोगों का कहना है कि नगरपालिका को चिन्हित क्षेत्र में कार्रवाई से पहले स्पष्ट करना चाहिए कि किस निर्माण को कितना हटाया जाना है और कार्रवाई कब से शुरू होगी। यदि लोगों को पर्याप्त समय दिया जाता है तो वे स्वयं उपयोगी सामग्री निकालकर सुरक्षित कर सकते हैं और मशीन से होने वाले अतिरिक्त नुकसान को भी कम किया जा सकता है।विकास जरूरी, लेकिन नुकसान कम होमॉडल रोड और चौड़ीकरण से शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन इसकी जद में आ रहे करीब 250 घर-दुकानों के कारण प्रभावित लोगों की चिंता भी सामने आ रही है। अब सबकी निगाह नगरपालिका की अगली कार्रवाई पर है। शहर विकास की राह पर बढ़े, लेकिन कार्रवाई ऐसी हो कि प्रभावित लोगों का नुकसान न्यूनतम रहे यही सबसे बड़ी अपेक्षा है।

धान पंजीयन में खसरा नंबर नहीं दिखने से किसान परेशान

मानपुर। धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया के बीच एक के बाद एक तकनीकी समस्याएं सामने आने से किसान परेशान हैं। पिछले तीन-चार दिनों से गिरदावरी की समस्या से जूझ रहे किसानों के सामने अब एग्री स्टैक पोर्टल पर खसरा नंबर प्रदर्शित नहीं होने की नई समस्या खड़ी हो गई है। किसानों का कहना है कि जब ऑपरेटर द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो एग्री स्टैक कंप्यूटर सिस्टम में संबंधित किसान का खसरा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके चलते पंजीयन केंद्रों पर किसानों की भीड़ बढ़ रही है और कई किसान घंटों इंतजार करने के बाद भी पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं। गौरतलब है कि शासन द्वारा धान खरीदी के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है। ऐसे में किसानों के पास पंजीयन कराने के लिए बेहद कम समय बचा है। लगातार तकनीकी दिक्कतों के चलते किसानों के बीच यह चिंता बढ़ती जा रही है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उनका पंजीयन कैसे पूरा होगा और उनकी उपज की सरकारी खरीदी हो पाएगी या नहीं।किसानों का कहना है कि पहले गिरदावरी से संबंधित समस्या के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ी और अब खसरा नंबर पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होने से पंजीयन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। किसानों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि एग्री स्टैक में खसरा नंबर प्रदर्शित नहीं होने की तकनीकी समस्या का तत्काल समाधान कराया जाए तथा पंजीयन की अंतिम तिथि को देखते हुए किसानों को पर्याप्त अवसर दिया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान धान की सरकारी खरीदी से वंचित न रह जाए।

कलेक्टर करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण

उमरिया। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 जनवरी 2027 तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय एवं सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह व्दारा ग्रामीण अंचलों का 9 अक्टूबर को भ्रमण किया जाएगा। मानपुर विकासखंड अंतर्गत पनपथा क्षेत्र के अधीनस्थ विभागीय कार्यालयों, छात्रावास, विद्यालय , अस्पताल, उचित मूल्य दुकान एवं अन्य संस्थाओं का निरीक्षण होगा तथा तदुपरांत दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक पनपथा में जन संवाद स्थल में विभागीय अधिकारी उपस्थित होकर अपने अपने विभाग के किए गए निरीक्षण की विस्तृत जानकारी से अवगत कराएंगे।

वार्ड 12 में पानी के लिए तरस रहे लोग, CM हेल्पलाइन में शिकायत का 'निराकरण' कागजों पर!

नगर परिषद बकहो की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, समस्या जस की तस, शिकायत बंद



अमलाई। नगर परिषद बकहो के वार्ड क्रमांक 12 में पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। रहवासियों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है और लोग लगातार परेशानी झेल रहे हैं। पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लिए लोगों को शिकायत का सहारा लेना पड़ा और इसी उम्मीद में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई कि शासन की निगरानी में उनकी समस्या का समाधान होगा।लेकिन रहवासियों के अनुसार, यहां कहानी कुछ और ही नजर आ रही है। पानी की समस्या का समाधान जमीन पर हुआ नहीं, लेकिन सीएम हेल्पलाइन में शिकायत का निराकरण जरूर हो गया।यही सबसे बड़ा सवाल है—जब लोगों को पानी मिल ही नहीं रहा, तो शिकायत का समाधान आखिर किस बात का हुआ?सीएम हेल्पलाइनः शिकायत जनता की, निराकरण अधिकारी की मर्जी से?सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य यही है कि आम नागरिक स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होने पर शासन तक अपनी आवाज पहुंचा सके। लेकिन यदि शिकायत दर्ज कराने के बाद संबंधित विभाग ही अपनी रिपोर्ट लगाकर शिकायत बंद कर दे और शिकायतकर्ता से यह तक न पूछा जाए कि उसकी समस्या वास्तव में दूर हुई या नहीं, तो फिर इस पूरी व्यवस्था की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।वार्ड 12 के लोगों का आरोप है कि शिकायतकर्ता की जानकारी और संतुष्टि के बिना ही शिकायत बंद कर दी गई। अगर यह स्थिति सही है तो यह केवल पानी की समस्या नहीं, बल्कि शिकायत निवारण व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी सवाल है।पानी नहीं मिला, फिर किसका हुआ 'निराकरण' ?एक तरफ नागरिक पानी के लिए परेशान हैं। दूसरी तरफ सरकारी रिकॉर्ड में शिकायत का निराकरण दिखा दिया जाता है। ऐसे में आम आदमी के सामने बड़ा सवाल खड़ा होता है—क्या सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत का मतलब समस्या का समाधान है या सिर्फ शिकायत को बंद कर देना?अगर शिकायतकर्ता ही बता रहा है कि समस्या अभी भी मौजूद है, तो विभाग की रिपोर्ट और जमीनी हकीकत में इतना बड़ा अंतर क्यों?और यदि किसी शिकायत का समाधान हो चुका है, तो क्या शिकायतकर्ता से इसकी पुष्टि नहीं होनी चाहिए?गड्ढा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन असली गड्ढा व्यवस्था में है!पाइपलाइन की जांच के लिए खोदा गया गड्ढा निश्चित रूप से एक अलग समस्या है। उसमें गाय गिरने की घटना के बाद यह भी जरूरी है कि नगर परिषद उसे तत्काल सुरक्षित करे। हफ़्तों से खोदकर इसी प्रकार गड्ढा छोड़ दिया गया जिसमें मवेसी गिर कर घायल हो रहे है लेकिन वार्ड की मूल समस्या गड्ढा नहीं, पानी है।और सबसे बढ़कर, उनकी शिकायत पर वास्तविक कार्रवाई चाहिए।जनता का सवाल सीधा है—अगर हर शिकायत का समाधान अधिकारी अपनी रिपोर्ट में ही कर देंगे और शिकायतकर्ता से पूछा तक नहीं जाएगा, तो फिर सीएम हेल्पलाइन पर जनता अपनी समस्या लेकर जाए तो जाए कहां?सीएम हेल्पलाइन को शिकायत बंद करने का माध्यम नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत देने का माध्यम बनाया जाना चाहिए। वार्ड 12 के मामले में पानी की समस्या की जमीनी जांच कराकर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि शिकायत का निराकरण वास्तव में हुआ है या सिर्फ रिकॉर्ड में।



एसडीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न प्रशासन ने दिलाया शांतिपूर्ण त्योहारों का भरोसा

मानपुर। आगामी त्योहारों नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण माहौल एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरनीत कौर कलसी की अध्यक्षता में नगर पालिका मानपुर के सभाकक्ष में 08 अक्टूबर को सुबह 11 बजे उपखण्ड स्तरीय शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।बैठक में तहसीलदार मानपुर अभ्यानंद शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती रचियता अवस्थी,थाना प्रभारी गर्ग, सामाजिक संगठन,व्यापारी बंधु,विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग का अमला भी उपस्थिति रहा। बैठक में भाजपा जिला महामंत्री हरीश विश्वकर्मा जी,रसिक खंडेलवाल किसान मोर्चा जिला महामंत्री,अधिकारी विद्युत विभाग,अधिकारी स्वास्थ्य विभाग,सहित नगर के समस्त जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार बंधु राजू गुप्ता,अजय पयासी,रामाविलाश त्रिपाठी जय प्रकाश शर्मा उपस्थित रहे। बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान साफ-सफाई, विद्युत, पेयजल, यातायात, डीजे एवं लाउडस्पीकर के माननीय न्यायालय के नियमानुसार उपयोग, तथा असामाजिक तत्वों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। एसडीएम हरनीत कौर कलसी ने सभी जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकार साथियों से अपील की कि प्रशासन का सहयोग कर त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ सभी मिलकर मनाएं।

महीनों से खराब पड़ा ईएसआई औषधालय अमलाई का प्रिंटर, इलाज के साथ अब कागजी काम भी बना परेशानी

मेडिकल फिटनेस और जरूरी प्रपत्रों के लिए डॉक्टरों-बीमित कर्मचारियों को बाहर से प्रिंट निकलवाने की मजबूरी



अमलाई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई के औषधालय अमलाई में महीनों से प्रिंटर खराब पड़ा होने के कारण बीमित कर्मचारियों और औषधालय के स्टाफ को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि मेडिकल फिटनेस सहित अन्य जरूरी प्रपत्रों की प्रिंटिंग के लिए डॉक्टरों और कर्मचारियों को बाहर जाकर प्रिंट निकलवाना पड़ रहा है।औषधालय में आने वाले बीमित कर्मचारियों के लिए जहां स्वास्थ्य सेवाएं महत्वपूर्ण हैं, वहीं मेडिकल फिटनेस और अन्य दस्तावेज भी उनके कामकाज का जरूरी हिस्सा हैं। लेकिन प्रिंटर खराब होने के कारण अब इन सामान्य से कामों के लिए भी लोगों को औषधालय से बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है।महीनों से खराब है प्रिंटर, अब तक नहीं हुआ इंतजामऔषधालय के डॉक्टरों से जानकारी लेने पर सामने आया कि प्रिंटर लंबे समय से खराब है। बताया गया कि खराब प्रिंटर का आवश्यक सामान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि नया प्रिंटर भी ऊपर से अभी तक नहीं पहुंचा है।सवाल यह है कि जब विभाग को महीनों से पता है कि प्रिंटर खराब है और उसका उपयोग जरूरी दस्तावेजों के लिए होता है, तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई?क्या एक सरकारी औषधालय में एक प्रिंटर की खराबी के कारण महीनों तक काम प्रभावित होना सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा माना जाएगा?बीमित कर्मचारी परेशान, स्टाफ भी मजबूरप्रिंटर खराब होने का खामियाजा केवल औषधालय के कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि यहां आने वाले बीमित कर्मचारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। जिन दस्तावेजों की सुविधा औषधालय में ही मिलनी चाहिए, उनके लिए बाहर जाना पड़ रहा है।एक तरफ कर्मचारी अपने स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए ईएसआई औषधालय पहुंचते हैं, वहीं दूसरी तरफ जरूरी प्रपत्रों की प्रिंटिंग के लिए उन्हें बाहर भेजा जाना व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है।'प्रिंटर नहीं है'—क्या यही है व्यवस्था का जवाब?सबसे बड़ा सवाल यह है कि महीनों से प्रिंटर खराब होने की जानकारी होने के बावजूद नया प्रिंटर अब तक क्यों नहीं पहुंचा? यदि पुराने प्रिंटर का पार्ट नहीं मिल रहा था, तो तत्काल वैकल्पिक प्रिंटर की व्यवस्था क्यों नहीं की गई?सरकारी संस्थानों में छोटी-छोटी व्यवस्थागत कमियां अक्सर आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती हैं। अमलाई ईएसआई औषधालय का मामला भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, जहां एक प्रिंटर की खराबी ने कर्मचारियों और बीमितों दोनों को बाहर से प्रिंट निकलवाने के लिए मजबूर कर दिया है।अब देखना यह है कि ईएसआई के जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या को कब गंभीरता से लेते हैं और अमलाई औषधालय को नया प्रिंटर कब उपलब्ध कराया जाता है।

शासकीय महाविद्यालय बिरसिंहपुर पाली में मतदाता पंजीयन शिविर का शुभारंभ



बिरसिंहपुर पाली, 8 अक्टूबर 2026।शासकीय महाविद्यालय बिरसिंहपुर पाली में 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के उद्देश्य से 8 से 10 अक्टूबर 2026 तक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य श्री हरलाल अहिरवार की उपस्थिति में किया गया।कार्यक्रम में बीएलओ एवं मतदाता जागरूकता एम्बेसडर डॉ. शाहिद सिद्दीकी द्वारा विद्यार्थियों को मतदाता पंजीयन की प्रक्रिया, पात्रता तथा मतदान के महत्व के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी पात्र विद्यार्थी अपना नाम निर्वाचक नामावली में अवश्य जुड़वाएं तथा अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी मतदाता पंजीयन के लिए जागरूक करें।प्राचार्य श्री हरलाल अहिरवार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक की सहभागिता महत्वपूर्ण है। युवा वर्ग जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करे तथा अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करे।शिविर के दौरान पात्र विद्यार्थियों को मतदाता पंजीयन एवं नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने संबंधी आवश्यक प्रक्रिया और प्रपत्रों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।यह विशेष शिविर विद्यार्थियों में मतदाता जागरूकता एवं लोकतांत्रिक सहभागिता की भावना विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

सेवा सेतु अभियान: धनपुरी विद्युत वितरण केंद्र में लगा शिविर, 13 उपभोक्ताओं ने कराया 'सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' का पंजीयन





बुढ़ार। सब-डिवीजन के अंतर्गत विद्युत वितरण केंद्र परिसर धनपुरी में गुरुवार को 'सेवा सेतु अभियान' के तहत 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के विशेष शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में विद्युत वितरण केंद्र के सहायक अभियंता सुभाष सेन, विकास गोंदूडे, धनपुरी के कनिष्ठ अभियंता कामता पटेल एवं पार्षद कैलाश सोनकर मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान रजिस्ट्रेशन अधिकारी रवि कुशवाहा ने शिविर में पहुंचे उपभोक्ताओं को योजना के प्रावधानों, सब्सिडी और उससे मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़कर मुफ्त बिजली का लाभ पहुंचाना है। शिविर को लेकर स्थानीय उपभोक्ताओं में खासा उत्साह देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप 13 उपभोक्ताओं ने मौके पर ही योजना के अंतर्गत अपना पंजीयन कराया।

आयोजन में एस.ए. सोलर (हैवेल्स, अडानी, टाटा) के प्रतिनिधि राकेश पासवान व अभिषेक जायसवाल तथा अजहर एंटरप्राइजेज के एडवाइजर ने उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं को सोलर पैनलों की कार्यप्रणाली, गुणवत्ता और तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में जिले की 64 प्रतिशत पंचायतें हुई टीबी से मुक्त



उमरिया। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय के निर्देशन तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह के मार्गदर्शन में जिले की 64 प्रतिशत ग्राम पंचायते टीबी रोग से मुक्त हुई है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में राज्य स्तर पर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जिले की कुल 152 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्राप्त हुए है जिनमें से 13 ग्राम पंचायतों को स्वर्ण स्तर का , 44 ग्राम पंचायतों को रजत स्तर का तथा 95 ग्राम पंचायतों को कांस्य स्तर का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी उन्मूलन हेतु किए जा रहे सतत प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देशो के अनुपालन में जिले में जिला स्तरीय टीबी मुक्त भारत समिति का गठन किया गया है। टी.बी. के प्रति जागरूकता एवं जनभागीदारी को बढावा देने के उद्देश्य से जिले में जिला स्तर एवं विकासखंड स्तर पर जोश टीम का गठन किया गया है जिससे 5 माई भारत स्व यंसेवक एवं 5 एनसीसी कैडेट को शामिल किया गया है। जिनके नेतृत्व एक नामित प्रथम श्रेणी स्तर के नोडल अधिकारी रहेगे। नई दिल्ली से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिसका लाइव प्रसारण देखा गया। जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनुज पटेल , धनुष धारी सिंह, डिप्टी कलेक्टर प्रिया अग्रवाल ,राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मुकुल तिवारी , जिला कार्यक्रम प्रबंधक दसन पद्मम , एस पी गुप्ता एवं विभिन्न पंचायतों के सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि,सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तथा टीबी मुक्त हुई पंचायतो के सरपंच उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में कुल 35 ग्राम पंचायतें एवं वर्ष 2024 में 64 ग्राम पंचायते सिल्वर प्रमाण पत्र से सम्मानि हुई थी।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मतदान केंद्रों में हुआ विशेष शिविरों का आयोजन



उमरिया। जिले के दोनो विधानसभा क्षेत्रों बांधवगढ , मानपुर के मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र मतदाताओं, नवीन मतदाताओं के नाम जोडने के लिए शिविर का आयोजन प्रारंभ किया गया है । यह शिविर 9 अक्टूबर को भी लगाएं जाएंगे जिसमें बीएलओं व्दारा नवीन मतदाताओ के नाम तथा छूटे हुए मतदाताओ के नाम मतदाता सूची मे जोडने की कार्यवाही की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 8 अक्टूबर को आयोजित विशेष शिविर में सूची का परीक्षण कर छूटे हुए पात्र मतदाताओ की पहचान कर मतदाता सूची में नाम जोडने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई । इस दौरान महाविद्यालय उमरिया, महाविद्यालय पाली, मोहतराई, गोरैया, तुम्मीछोट, बाजाकुंड, नौरोजाबाद, नौगजा सहित मतदान केंद्रों में शिविरों का आयोजन किया गया। मतदान केन्द्र स्तर पर आयोजित इन शिविरों में बीएलओ द्वारा पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही रात्रि आश्रय स्थलों, श्रमिक बस्तियों एवं बेघर व वंचित व्यक्तियों के नाम भी नामावली में सम्मिलित किए जा रहे है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती राखी सहाय ने सभी बीएलओ को निर्देशित किया है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे। बीएलओ द्वारा अपने-अपने मतदान केन्द्र क्षेत्र में पात्र मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संबंधित आरओ एवं एआरओ द्वारा शिविरों तथा मतदाता सूची में नाम जोडने की प्रक्रिया की निरंतर मॉनीटरिंग की जा रही है। उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए किसी प्रकार का घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। पात्र मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। नवीन युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए महाविद्यालयों में भी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। महाविद्यालयों में आयोजित शिविरों में युवाओं में मतदाता बनने को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। छात्र-छात्राएं मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर रहे हैं।

खबर संक्षेप



बैंक अधिकारी बनकर 1.36 लाख की साइबर ठगी

कोतमा। नगर में साइबर ठगी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जालसाज नए-नए तरीके अपनाकर व्यापारियों, शासकीय सेवकों सहित आम नागरिकों की मेहनत की कमाई को निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नगर के वार्ड क्रमांक 12 गोविंदा कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय रमाकांत पांडे के साथ सामने आया है, जहां शातिर जालसाज ने खुद को एसबीआई योनो बैंक का अधिकारी बताकर बैंकिंग एप चालू कराने का झांसा दिया और उनके खाते से 1 लाख 36 हजार 500 रुपए पार कर दिए। बताया गया कि रमाकांत पांडे के मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को एसबीआई योनो का अधिकारी बताते हुए योनो बैंकिंग सुविधा चालू कराने की बात कही। इसके बाद जालसाज ने व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ फाइल भेजीं और उन्हें खोलकर बताए गए तरीके से प्रक्रिया पूरी करने को कहा। पीड़ति द्वारा जालसाज के बताए अनुसार प्रक्रिया करने के दौरान ओटीपी और लिंक साझा किए गए। इसके बाद कुछ ही समय में उनके बैंक खाते से अलग-अलग किस्तों में 99,500 रुपए, 15,000 रुपए और 22,000 रुपए, कुल 1,36,500 रुपए ट्रांसफर हो गए। खाते से बड़ी रकम निकलने की जानकारी मिलते ही रमाकांत पांडे के होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल कोतमा स्थित बैंक शाखा पहुंचकर बैंक प्रबंधन को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी और संबंधित मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ धारा 318(4) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा ठगी की रकम के ट्रांजैक्शन, मोबाइल धारक और खाते की जानकारी जुटा रही है।

प्रेशर हॉर्न पर यातायात पुलिस सख्त, तीन दिन चलेगा विशेष अभियान



अनूपपुर। बसों और अन्य वाहनों में नियम विरुद्ध लगाए जाने वाले प्रेशर हॉर्न के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब (आईपीएस) के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा जिले में तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बसों सहित अन्य वाहनों की सघन जांच कर प्रेशर हॉर्न पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस को वाहनों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। तेज और कर्कश आवाज वाले इन हॉर्न से आम लोगों को परेशानी होने के साथ सड़क पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अब विशेष अभियान के जरिए ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। यातायात पुलिस ने जिले के सभी बस संचालकों और वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि वे अपने वाहनों की जांच कर लें। यदि वाहन में नियम विरुद्ध प्रेशर हॉर्न लगा है तो उसे तत्काल निकलवा लें। अभियान के दौरान प्रेशर हॉर्न पाए जाने पर संबंधित वाहन के खिलाफ नियमानुसार भारी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने वाहन संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप ही हॉर्न का इस्तेमाल करें। यातायात पुलिस का कहना है कि अभियान का उद्देश्य कार्रवाई के साथ चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

थार की चमक, गांजे का धंधा और 'बड़े दादा' का खेल

जेल में कई आरोपी, फिर भी गांव-गांव नशे की पहुंच पर सवाल





पकड़े जा रहे छोटे मोहरे, असली सप्लायर और नेटवर्क संचालक तक कब पहुंचेगी पुलिस?

अनूपपुर। आदिवासी बहुल अनूपपुर में गांजे के कथित कारोबार को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिले में गांजा तस्करी और बिक्री के मामलों में कई आरोपी पकड़े गए, प्रकरण दर्ज हुए और आरोपी जेल भी पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों में नशे की उपलब्धता को लेकर शिकायतें और चर्चाएं थम नहीं रही हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं कि पुलिस ने कितने आरोपियों को पकड़ा, बल्कि यह है कि गांजा आखिर पहुंचा कौन रहा है और उसके पीछे बैठा नेटवर्क कौन चला रहा है? जिले में यदि एक के बाद एक आरोपी पकड़े जाने के बाद भी सप्लाई की कड़ी पूरी तरह नहीं टूट रही है तो कहीं न कहीं कार्रवाई अभी नेटवर्क की निचली परत तक ही सीमित तो नहीं है। सामान के साथ पकड़ा गया व्यक्ति सामने दिखाई देता है, लेकिन उसे माल उपलब्ध कराने वाला, पैसा लगाने वाला, वाहन उपलब्ध कराने वाला और स्थानीय स्तर पर बिक्री का नेटवर्क खड़ा करने वाला पर्दे के पीछे रह जाता है। यही वह कड़ी है, जिस तक पहुंचना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

जेल में आरोपी, फिर भी सप्लाई कैसे?

गांजा तस्करी के मामलों में गिरफ्तारियां लगातार होने के बावजूद यदि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता की शिकायतें बनी हुई हैं तो पुलिस को सप्लाई लाइन की पूरी पड़ताल करनी होगी। एक आरोपी जेल जाता है और कुछ समय बाद दूसरा चेहरा सामने आता है तो यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या नेटवर्क में नए मोहरे तैयार किए जा रहे हैं? मुख्य मार्ग पर वाहन रोककर गांजा पकड़ना कार्रवाई का एक हिस्सा है, लेकिन असली जांच वहां से शुरू होती है कि माल आया कहां से, किसके संपर्क से आया, भुगतान किसने किया और आगे किसे पहुंचाया जाना था। यदि जांच इन सवालों तक नहीं पहुंचती तो कार्रवाई का असर केवल तत्काल गिरफ्तारी तक सीमित रह सकता है।

गांवों तक पहुंची नशे की चर्चा, निगरानी कितनी?

शहर और मुख्य मार्गों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी गांजे की उपलब्धता की चर्चाएं सामने आती हैं। दूरस्थ आदिवासी अंचलों के ग्रामीण रास्ते, छोटे बाजार, ढाबे और सुनसान स्थान ऐसे क्षेत्र हैं जहां पुलिस की नियमित निगरानी कितनी प्रभावी है, यह भी जांच का विषय है। नशे के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई का पैमाना केवल जब्ती और गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। यह भी देखना जरूरी है कि गिरफ्तारी के बाद उस आरोपी से जुड़े संपर्कों की कितनी पड़ताल हुई और उसके पीछे मौजूद सप्लाई चैन तक पुलिस पहुंची या नहीं।

थार की चमक, अचानक बदली जिंदगी भी जांच का विषय

ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में कुछ युवाओं की अचानक बदली जीवनशैली भी चर्चा का विषय बनती है। महंगी गाड़ियां, महंगे मोबाइल और खर्चीले रहन-सहन का प्रदर्शन अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की घोषित आय और उसकी जीवनशैली में बड़ा अंतर दिखाई देता है तो उसकी आय के स्त्रोत की जांच करना जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है। गाड़ी किसके नाम है, उसका उपयोग कौन कर रहा है, पैसा कहां से आया, किन लोगों से संपर्क हैं और संदिग्ध गतिविधियों से कोई संबंध तो नहीं इन सवालों की पड़ताल से कई छिपी कड़ियां सामने आ सकती हैं। इसलिए जांच का केंद्र सिर्फ गांजे की खेप नहीं, बल्कि उस खेप के पीछे घूमने वाला पैसा भी होना चाहिए।

छोटे मोहरे जेल में, 'बड़ा दादा' कौन?

नशे के कथित कारोबार में सबसे पहले वही व्यक्ति पुलिस की पकड़ में आता है, जो माल के साथ मिलता है। लेकिन उसके बाद जांच की असली परीक्षा शुरू होती है। माल किसने दिया? पैसा किसने लगाया? संपर्क किसने कराया? वाहन किसने उपलब्ध कराया? बिक्री का स्थानीय नेटवर्क किसके नियंत्रण में है? इन सवालों के जवाब यदि जांच में सामने नहीं आते तो कार्रवाई सिर्फ निचली कड़ी तक सीमित मानी जाएगी। पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल संपर्क, लेनदेन, पुराने आपराधिक संबंध और उनसे जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल करनी होगी। तभी यह पता चल सकेगा कि कहीं छोटे तस्करों के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा।

अब गिरफ्तारी नहीं, नेटवर्क तोड़ने की चुनौती

अनूपपुर में नशे के खिलाफ कार्रवाई को अब केवल धरपकड़ और जब्ती के आंकड़ों से आगे ले जाने की जरूरत है। ग्रामीण स्तर पर खुफिया तंत्र मजबूत करना, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना जुटाना, सप्लाई चैन की कड़ियां जोड़ना और संदिग्ध आर्थिक लेनदेन की जांच करना जरूरी है। क्योंकि सवाल एक आरोपी के जेल जाने का नहीं है। सवाल यह है कि उसके जेल जाने के बाद उसी जगह दूसरा व्यक्ति गांजा लेकर कैसे पहुंच जाता है? पुलिस को अब यह तलाशना होगा कि नशे की इस कथित सप्लाई लाइन की शुरुआत कहां से होती है और पैसा आखिर किस तक पहुंचता है। जब तक जड़ तक हाथ नहीं पहुंचेगा, तब तक शाखाओं की कटाई से नशे का कारोबार पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं है। अब सवाल सीधा है छोटे मोहरे तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन असली सप्लायर और नेटवर्क संचालक कब गिरफ्त में आएंगे।

सेवा समाप्ति, निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में जिला पटवारी संघ ने खोला मोर्चा



कार्रवाई नहीं रुकी तो ऑनलाइन राजस्व काम से विरत रहेंगे पटवारी

अनूपपुर। पटवारियों के खिलाफ सेवा समाप्ति, निलंबन और अन्य दंडात्मक कार्रवाई को लेकर मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने अब प्रदेशव्यापी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। देवास जिले में 'स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026' के कार्यों को लेकर की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए अनूपपुर जिला पटवारी संघ ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव और कलेक्टर को ज्ञापन भेजा है। संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि पटवारियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो पटवारी ऑनलाइन राजस्व कार्यों से विरत रहेंगे। जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष चेतन सिंह मरावी और मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष उपेंद्र सिंह चौहान की ओर से 8 अक्टूबर को जारी पत्र में कहा गया है कि देवास जिले में स्वामित्व योजना से संबंधित कार्यों के आधार पर पटवारी साथियों के खिलाफ सेवा समाप्ति, निलंबन एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। संघ का दावा है कि स्वामित्व योजना के निष्पादन से जुड़ी विधिक और व्यवहारिक समस्याओं से शासन को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका था। इसके बावजूद कार्रवाई किए जाने को संघ ने चिंताजनक बताया है।

7 अक्टूबर से ऑनलाइन काम से विरत रहने का निर्णय

पटवारी संघ ने अपने पत्र में प्रदेश संगठन के निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि 7 अक्टूबर से प्रदेश के समस्त पटवारी संवर्ग ऑनलाइन राजस्व कार्यों से विरत रहेंगे। इतना ही नहीं, पटवारियों ने सभी शासकीय समूहों से भी बाहर रहने का निर्णय लिया है। संघ के अनुसार यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक संबंधित दंडात्मक कार्रवाई वापस नहीं ली जाती। इसका सीधा असर राजस्व विभाग से जुड़े उन कामों पर पड़ सकता है, जिनमें पटवारियों की ऑनलाइन भूमिका महत्वपूर्ण है। जमीन से संबंधित रिकॉर्ड, विभिन्न राजस्व प्रकरणों की कार्यवाही और ऑनलाइन प्रविष्टियों सहित कई काम पटवारी स्तर पर किए जाते हैं। ऐसे में यदि विरोध लंबा खिंचता है तो आम लोगों के राजस्व संबंधी काम भी प्रभावित होने की आशंका है।

भविष्य में किसी जिले में कार्रवाई हुई तो प्रदेशभर में विरोध

संघ ने अपने पत्र में भविष्य के आंदोलन को लेकर भी स्पष्ट रुख अपनाया है। कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी जिले में पटवारियों के विरुद्ध इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई की जाती है तो उसकी सूचना प्रदेश के सभी पटवारियों को दी जाएगी। इसके बाद समस्त पटवारी बिना पूर्व सूचना के ऑनलाइन राजस्व कार्यों से विरत होंगे। इस तरह संघ ने एक जिले की कार्रवाई को प्रदेश के पटवारी संवर्ग से जोड़ दिया है। इससे आने वाले दिनों में राजस्व विभाग और पटवारी संघ के बीच टकराव बढ़ने की संभावना बन गई है।

देवास की कार्रवाई वापस लेने की मांग

ज्ञापन में जिला पटवारी संघ ने देवास जिले में की गई सेवा समाप्ति तथा अन्य जिलों में की गई निलंबन एवं दंडात्मक कार्रवाई को तत्काल वापस लेने की मांग की है। संघ ने राजस्व विभाग से मामले में आवश्यक कार्रवाई कर शासन स्तर पर लिए गए निर्णय की जानकारी देने का अनुरोध किया है। अब नजर इस बात पर है कि शासन पटवारी संघ की चेतावनी पर क्या रुख अपनाता है। यदि कार्रवाई वापस नहीं होती है और पटवारी ऑनलाइन राजस्व कार्यों से लगातार विरत रहते हैं, तो इसका सीधा असर आम लोगों के राजस्व संबंधी कामकाज पर पड़ सकता है।

माइंस से बाहर कॉलोनी में मिट्टी डंप करने की नहीं अनुमति, फिर कैसे बाहर निकला ट्रक?'

राजनगर।



नगर परिषद डोला के वार्ड क्रमांक 15 स्थित सी-सेक्टर कालोनी के मुख्य गेट पर डोला नगर परिषद द्वारा लगाए गए काउ कैचर के एक हैवी वाहन से क्षतिग्रस्त होने के बाद ओपन कास्ट खदान से निकलने वाले वाहनों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। शिकायत के अनुसार, 6 अक्टूबर को राजनगर खुली खदान परियोजना से (ओपन कास्ट क्षेत्र) से मिट्टी लदा एक हैवी वाहन सी-सेक्टर कालोनी के अंदर पहुंचा। वाहन के गुजरने के दौरान काउ कैचर क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन का वीडियो भी शिकायत के साथ संलग्न किया गया है। मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है, कि यदि माइंस क्षेत्र से निकलने वाली मिट्टी को खदान के निर्धारित डंपिंग क्षेत्र में ही डाला जाना है और माइंस क्षेत्र से बाहर कालोनी में मिट्टी डंप करने की अनुमति नहीं है, तो फिर मिट्टी से लदा ट्रक खदान क्षेत्र से बाहर निकलकर सी सेक्टर कॉलोनी तक कैसे पहुंचा? क्या संबंधित ट्रक को माइंस से बाहर जाने की अनुमति दी गई थी? यदि अनुमति थी, तो किस उद्देश्य से? और यदि अनुमति नहीं थी तो वाहन माइंस से बाहर कैसे निकला? इन सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों और प्रबंधन की जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। मामला सिर्फ काउ कैचर टूटने तक सीमित नहीं है। यदि खदान से निकलने वाले वाहनों की निर्धारित रूट और डंपिंग स्थल के स्तर पर निगरानी की जाती है, तो फिर ऐसा वाहन कॉलोनी के अंदर तक कैसे पहुंच गया? क्या वाहन की एंट्री-एग्जिट और उसमें लदी सामग्री का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था? यह भी जांच का विषय है। माइंस के अंदर से मिट्टी लदे वाहनों के बाहर निकलने की घटना के बाद स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठ रहा है, कि कहीं मिट्टी की आड़ में किसी अन्य सामग्री को तो बाहर नहीं ले जाया जा रहा। क्या रात के समय भी ऐसे वाहनों की आवाजाही होती है और क्या उनकी जांच की जाती है? हालांकि, इस तरह की आशंका की पुष्टि बिना जांच के नहीं की जा सकती। ऐसे में पूरे मामले में वाहन की पहचान, माइंस से बाहर निकलने का समय, वाहन का रूट, लदी हुई सामग्री, डंपिंग स्थल तथा संबंधित अनुमति और रिकॉर्ड की जांच जरूरी है। अब देखना होगा कि प्रबंधन और संबंधित एरिया इस मामले की जांच कराकर यह स्पष्ट करते हैं या नहीं कि माइंस क्षेत्र से बाहर मिट्टी लदा ट्रक किस अनुमति के आधार पर कॉलोनी तक पहुंचा और वहां मिट्टी डंप करने की अनुमति किसने दी।

इनका कहना है

हम ट्रक का पता लगा रहे हैं, संबंधित विभाग को पत्राचार कर चुके हैं। ट्रक का पता लगाने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

सुमित कौशिक
थाना प्रभारी रामनगर

नवरात्रि, दशहरा और दीपावली पर शांति-सौहार्द्र बनाए रखने की अपील कलेक्टर ने शांति समिति की बैठक में दिए निर्देश

एसपी बोले-त्योहारों में पुलिस-प्रशासन का करें सहयोग

अनूपपुर। आगामी नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर रत्नाकर झा की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब की मौजूदगी में हुई बैठक में पर्वों के दौरान कानून व्यवस्था, यातायात, सुरक्षा, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। समिति सदस्यों से सुझाव भी लिए गए। कलेक्टर रत्नाकर झा ने जिलेवासियों से सभी त्योहार आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने नवरात्रि के दौरान दुर्गा प्रतिमाओं के पंडाल सड़क पर नहीं लगाने तथा यातायात को ध्यान में रखते हुए निर्धारित और उपयुक्त स्थानों पर ही पंडाल स्थापित करने के निर्देश दिए। पंडालों में विद्युत व्यवस्था के लिए वैध कनेक्शन लेना अनिवार्य रहेगा।

विसर्जन मार्ग और प्रकाश व्यवस्था पर जोर

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विसर्जन मार्ग और यातायात व्यवस्था को पहले से व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। विसर्जन स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के लिए जनरेटर की व्यवस्था करने तथा अधिकारियों-कर्मचारियों की नामवार ड्यूटी लगाने को कहा गया। वरिष्ठ अधिकारियों को व्यवस्थाओं का निरीक्षण और सतत निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने सभी दुर्गा समितियों को समिति के सदस्यों की जानकारी संबंधित थानों में उपलब्ध कराने तथा पंडालों में सुरक्षा संबंधी निर्धारित मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। नगरीय क्षेत्रों में साफ-सफाई, सड़कों की मरम्मत और गड्ढों के भराव के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिए गए।

पंचमी से बढ़ेगा यातायात दबाव

बैठक में बताया गया कि नवरात्रि की पंचमी से ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु नगरों में दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इससे प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए कलेक्टर ने प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था और सुगम यातायात के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। बिजुरी नगर में हनुमान मंदिर से एलआईसी कार्यालय तक पार्किंग की समस्या का मुद्दा भी बैठक में उठा। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।



रावण दहन में सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी

दशहरा पर्व पर आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थलों पर कानून व्यवस्था, यातायात एवं पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रावण दहन शासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराने पर जोर दिया गया। दीपावली के दौरान लगने वाली पटाखा दुकानों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। कलेक्टर ने एसडीएम अनूपपुर, एसडीओपी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को संयुक्त रूप से उपयुक्त स्थलों का चिन्हांकन कर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। पटाखा दुकानों के लिए शासन के सुरक्षा मापदंडों के अनुरूप ही स्थान आवंटित किया जाएगा। साथ ही अग्नि सुरक्षा, यातायात और आमजन की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें नागरिक-एसपी

पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब ने जिलेवासियों से नवरात्रि, दशहरा और दीपावली पर्व आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। शांति समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों तथा शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। सभी विभागों को भी अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के निर्देश दिए गए, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सकें। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्चना कुमारी, अपर कलेक्टर बलवीर रमन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम, एसडीएम अनूपपुर प्राशी अग्रवाल सहित शांति समिति के सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।